HINDUSTAN TIMES, LUCKNOW
MONDAY, NOVEMBER 10, 2014

Adopt a village each, farm scientists urged

AGRI MINISTER APPEAL Propagate knowledge among villagers

HT Correspondent
lkoreportersdesk@hindustantimes.com

LUCKNOW: Union agriculture minister Radha Mohan Singh on Sunday appealed to agricultural scientists of various research institutes to adopt one village each to propagate their knowledge to villagers.

Addressing scientists at the Indian Institute of Sugarcane Research here, the minister said, "Every scientist should adopt at least one village, whether it's their own or in some place else. If 7,000 scientists adopt one village each, it can bring about a big change in the agriculture sector."

Singh said agriculture was the lifeline of the country and if India was to be strengthened, then boosting agriculture was the way to do it. "Research being done in institutes should reach villages so that farmers can make the best use of it. Gujarat is the country's most developed state and one big reason for this is its advanced agriculture. The agriculture development rate in Gujarat has been between 11 % and 12 % in the past few years as opposed to the country's national average of just 4%," he said.

> RESEARCH BEING DONE IN INSTITUTES SHOULD REACH VILLAGES SO THAT FARMERS CAN MAKE THE BEST USE OF IT
> RADHA MOHAN SINGH, Union agriculture minister

He also enquired from the scientists about the achievements and problems of their institutes and assured them that vacant posts would be filled within a year.

The minister said the central government was planning to appoint 1000 scientists in agriculture research institutes in the country by 2015 while appointment of another 300 was presently in the pipeline.

Assuring the UP government of extending all support for agriculture development, the minister said Uttar Pradesh could get the country's first breeding centre if the state government was willing. He said the land for this centre would be required near Delhi.

On relief package for drought hit areas in UP, Singh told reporters that certain information has been sought. "The Central team has made assessment of farm loss in the drought-affected areas in the state, but certain information has been sought from the government which has not been received yet," he said.

कृषि वैज्ञानिक भी एक-एक गांव गोद लें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने वैज्ञानिकों से खेती-किसानी की तरक्की को एक-एक गांव गोद लेने का आह्वान किया। सपा सरकार पर सकारात्मक सहयोग नहीं देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसी कारण उप्र की कृषि विकास दर में सुधार नहीं हो रहा है।

रविवार को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में कृषि वैज्ञानिकों,विश्वविद्यालयों व कृषि विकास केंद्रों की समीक्षा बैठक में पूरे होमवर्क के साथ पहुंचे कृषि मंत्री के सवालों के उत्तर में अधिकारी फंसते नजर आए। कृषि विकास केंद्र में कितने ट्रैक्टर व जीप खराब पड़े हैं, इसका जवाब अधिकारी नहीं दे सके। खुद मंत्री ने बताया कि कुल 40 ट्रैक्टरों में से 19 खराब है। करीब दो घंटे चली क्लास में कृषि मंत्री ने शोध कार्यों एवं विकास योजनाओं का लाभ किसानों को न मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वैज्ञानिकों को सलाह दी कि वे अपना या किसी मित्र के गांव के गोद लेकर किसानों को अपने ज्ञान और अनुभवों का लाभ दें। उनका कहना था कि सपा सरकार के असहयोग के बावजूद केंद्र सरकार कृषि विकास के लिए हरसंभव मदद राजनीति से हट कर करेगी। वर्ष 2015 तक शोध संसाधनों में 1000 वैज्ञानिकों की बहाली कर दी जाएगी। उप्र में जिन सात जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना नहीं हो सकी वहां भूमि मिले तो एक वर्ष निर्माण शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। कृषि मंत्री ने मछली व पशुपालन से लेकर बागवानी आदि के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया।

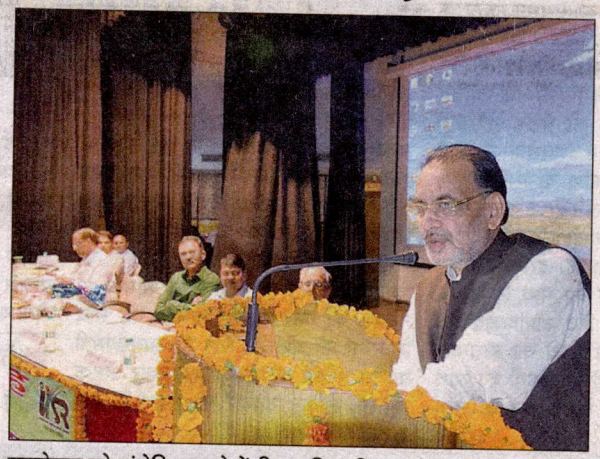

सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह

प्रथम ब्रीडिंग सेंटर उप्र में संभव

देसी प्रजाति के पशुओं की नस्ल सुधार के लिए देश का पहला ब्रीडिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में स्थापित हो सकता है बशर्ते सरकार दिल्ली के सौ किलोमीटर के दायरे में आवश्यक जमीन उपलब्ध कराए। कृषि मंत्री ने

- केंद्रीय कृषि मंत्री ने सपा सरकार पर लगाया असहयोग का आरोप

बताया कि मथुरा स्थित गाय अनुसंधान केंद्र के नवीनीकरण का प्रोजेक्ट तैयार करने में उप्र सरकार देरी कर रही है। प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो केंद्र सरकार तत्काल कार्यवाही शुरू करा देगी और उप्र का कोई पैसा खर्च नहीं होगा। उन्होंने पूर्वी उप्र में जैविक खेती के आधार पर दूसरी हरित क्रांति सफल बनाने पर बल दिया। उन्होंने जीएम बीज के प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे टाल दिया।

सूखे की नहीं मिली पूरी सूचना

उप्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में केंद्र की टीमों द्वारा दौरा करने के बावजूद कोई राहत न मिलने के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सूखे बारे में सम्पूर्ण जानकारियां उपलब्ध नहीं करायी है। इस कारण केंद्र राहत नहीं देने को विवश है। गोकुल मिशन में उप्र के पिछड़ने पर उन्होंने सरकार की उदासीनता को दोषी ठहराया।

पायनियर
लखनऊ, सोमवार, 10 नवंबर, 2014

गांव को गोद लेकर विज्ञान को किसान तक पहुंचाएं वैज्ञानिक

राज्य सरकार को कृषि अनुसंधान में देंगे मदद: राधामोहन

प्रदेश सरकार चाहे तो यूपी में खुल सकता है देश का पहला नेशनल ब्रीडिंग सेंटर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज देश के छह हजार से अधिक वैज्ञानिकों का अवाहन किया कि वो अपने गांव या फिर अपने नजदीक के किसी गांव को गोद लें और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नये अनुसंधान और नयी जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने का माध्यम बनें। राधामोहन सिंह आज लखनऊ के भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के दौरे पर थे और यहां पर कृषि क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़े तमाम संगठनों के अधिकारियों और वैज्ञानिकों से मुखातिब थे।

कृषि मंत्री ने विभिन्न कृषि अनुसंधान संगठनों और विभिन्न किसान विज्ञान केन्द्रों के अधिकारियों से उनके कार्यक्षेत्र की उपलब्धियों और समस्याओं की भी जानकारी ली।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने उत्तर प्रदेश को कृषि से जुड़े अनुसंधान का केन्द्र बनाने के लिए सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। कृषि मंत्री ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार दिल्ली के सौ किलोमीटर के दायरे में जमीन मुहैया कराये तो वह देश का पहला नेशनल ब्रीडिंग सेंटर भी यूपी में खोलने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यूपी के झांसी में केन्द्रीय कृषि विवि भी अब पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुका है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि देश की जीवन रेखा है, अगर देश को मजबूत करना है तो कृषि से जुड़े गाँव, किसान व संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी वैज्ञानिकों, शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी-अपनी जिम्मेदारी परिवार के तरह निभाना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों को विकास की दौड़ में यदि आगे आना है तो उन्हें कृषि विकास दर को गतिप्रदान करने की जरूरत होगी। इस संदर्भ में भारत सरकार का कृषि मंत्रालय देश के हर राज्यों को हर संभव सहायता करने को तैयार है। इस अवसर पर उन्होनें यह भी बताया कि 2015 तक कृषि शोध संस्थानों में लगभग 1000 वैज्ञानिकों की बहाली की जाएगी और तत्काल 300 वैज्ञानिकों की बहाली की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों को संसाधनों से समृद्ध बनाने पर जोर दिया तथा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र नही हैं और जल्द ही इन जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रो की स्थापना की जाएगी। हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक ट्रैक्टर, एक जीप तथा दो मोटर साइकिल आवश्यक रूप से उपलब्ध होने पर जोर दिया। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा. सुशील सोलोमन ने बताया कि संस्थान देश में गन्ना तथा चीनी उद्योग को खुशहाल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

जनसंदेश टाइम्स
लखनऊ, सोमवार, 10 नवम्बर 2014

कृषि को मजबूत करने की आवश्यकता: राधा मोहन

लखनऊ। केन्द्रीय कृषि ,खाद्य एवं सहकारिता मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि कृषि देश की जीवन रेखा है, अगर दे को मजबूत करना है तो कृषि से जुड़े गॉव, किसान व संस्थाओं को मजबूत करने की जरुरत है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी वैज्ञानिकों, शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी-अपनी जिम्मेदारी परिवार के तरह निभाना होगा। आज गुजरात देश का सबसे विकसित राज्य है इसमें कृषि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि गुजरात में पिछले कुछ वर्षो में कृषि विकास 11 से 12 प्रतिशत की दर से हुआ है वही दे में औसत कृषि विकास दर 4 प्रतिशत से भी कम रहा है। इससे यह स्पष्ट है उत्तर प्रदे तथा अन्य राज्यों को विकास की दौड़ में यदि आगे आना है तो उन्हें कृषि विकास दर को गति प्रदान करने की जरुरत होगी।

श्री सिंह रविवार को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान परिसर का दौरा करते हुए गन्ना शोध एवं उत्तर प्रदेश में स्थित अन्य कृषि शोध संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किये जा रहे कार्यो का निरीक्षण किया।

इस अवसर पर उन्होनें यह भी बताया कि सन् 2015 तक कृषि शोध संस्थानों में लगभग 1000 वैज्ञानिकों की बहाली की जाएगी और तत्काल 300 वैज्ञानिकों की बहाली की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होनें कृषि विज्ञान केंद्रों को संसाधनों से समृद्ध बनाने पर जोर दिया तथा उत्तर प्रदेा के 7 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र नही हैं और जल्द ही इन जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रो की स्थापना की जाएगी। हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक ट्रैक्टर, एक जीप तथा दो मोटर साइकिल आवयक रुप से उपलब्ध होने पर जोर दिया।

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा. सुशील सोलोमन ने संस्थान द्वारा विकसित गन्ना उत्पादन तकनीकों पर श्री सिंह को जानकारी से अवगत कराया । उन्होनें बताया कि संस्थान देश में गन्ना तथा चीनी उद्योग को खुशहाल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और इस पर मंत्री ने संतोष जताया। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति डा. मुन्ना सिंह

दौरा

केन्द्रीय मंत्री ने किया संस्थान का निरीक्षण, 2015 में 1000 कृषि वैज्ञानिकों की बहाली की जाएगी

ने प्रदेश में किये जा रहे कृषि कार्यो से मंत्री को अवगत कराया। आई सी ए आर शोध संस्थानों के निदेशक डा. जे. के. जेना, डॉ. एन. पी. सिंह, डा. वी. के. मिश्रा, डा. ए. के. मिश्रा ने संस्थानों द्वारा विकसित तकनीकों तथा प्रगति पर जानकारी प्रस्तुत किये।

संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डा. ए. के. साह ने बताया कृषि को आगे ले जाने के लिए किसानों की आवयकता तथा बदलते परिवेा के हिसाब से शोध कार्य कर तकनीक विकसित करने की जरुरत है इसी संदर्भ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित गन्ना उत्पादन तकनीकों को माननीय मंत्री जी ने संस्थान के प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर निरीक्षण किया तथा आगे और लाभकारी तकनीकों गन्ने में गड्ढा एवं नाली विधि से बुवाई, बड चिप तकनीक से बीज में बचत, स्किप कूड़ विधि से सिंचाई जल में लगभग 36 प्रतिात तक की बचत, पेड़ी प्रबंधन तकनीक से मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ पेड़ी गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि, किसानो के लिए गन्ने की खेती का पूर्ण यंत्रीकरण, कटर प्लांटर के अलावा केन हारवेस्टर के माडल का विकास, जैविक कीट नियंत्रण से किसानो को गन्ने की खेती को लाभान्वित बनाना तथा नई प्रजातियों जैसे को.लख. 94184 एवं यहॉ से विकसित अन्य प्रजातियाँ जैसे को.लख. 9709 एवं को.लख 07201 शर्करा की परता में वृद्धि के प्रयास विशेष उपलब्धियां रही हैं। जिससे प्रदेश एवं देश में गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि के अतिरिक्त लागत में कमी भी संभव है।

समेकित कीट प्रबंध के लिए संस्थान ने ट्राइकोकार्ड एवं फेरोमोन ट्रैप भी बनाए हैं जो विभिन्न चीनी मिलों में प्रदर्शित कर किसानों द्वारा लाभदायक सिद्ध हुए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी संस्थान में गन्ना प्रक्षेत्र प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्य उद्देश्य भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर 11 प्रतिशत चीनी का परता तथा उपोष्ण क्षेत्रों में 100 टन प्रति की उत्पादकता सुनिश्चित करना है। *वसं.*

2
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
डेली न्यूज़ ऐक्टिविस्ट
लखनऊ, सोमवार, 10 नवंबर 2014

वर्ष 2015 तक एक हजार वैज्ञानिकों की होगी भर्ती : कृषि मंत्री

लखनऊ (डीएनएन)। आज गुजरात देश का सबसे विकसित राज्य इसलिए बना है क्योंकि इसका कृषि में सबसे अहम योगदान है। पिछ्ले कुछ वर्षो में यहां की कृषि विकास दर 11 से 12 प्रतिशत तक रही है, जबकि देश में औसत कृषि विकास दर चार प्रतिशत से भी कम पाई गई है। इससे यह साफ होता है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को विकास की दौड़ में यदि आगे आना है, तो उन्हें कृषि विकास दर में तेजी लानी होगी। यह बात रविवार को भारतीय गन्ना अनंसुधान संस्थान में भारत सरकार के केंद्रीय कृषि, खाद्य एवं सहकारिता मंत्री राधा मोहन सिंह ने कही।

- **गुजरात की विकास दर 12, तो देश की सिर्फ चार प्रतिशत**

उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 तक कृषि शोध संस्थानों में लगभग 1000 वैज्ञानिकों की बहाली की जाएगी और तत्काल 300 वैज्ञानिकों की बहाली की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होनें कृषि विज्ञान केंद्रों को संसाधनों से समृद्ध बनाने पर जोर दिया। साथ ही सूबे के सात जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र नही हैं और जल्द ही इन जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक ट्रैक्टर, एक जीप और दो मोटर साइकिल उपलब्ध होने पर जोर दिया। संस्थान के निदेशक डॉ. सुशील सोलोमन ने संस्थान की ओर से विकसित गन्ना उत्पादन तकनीकों पर केंद्रीय मंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि संस्थान देश में गन्ना और चीनी उद्योग को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विवि के कुलपति डा. मुन्ना सिंह, आईसी. ए. आर. शोध संस्थानों के निदेशक डॉ. जेके. जेना, डॉ. एनपी. सिंह, डॉ. वीके मिश्रा, डॉ. एके. मिश्रा ने संस्थानों द्वारा विकसित तकनीकों और प्रगति पर जानकारी पेश की। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एके. साह ने बताया कृषि को आगे ले जाने के लिए किसानों की जरूरत और बदलते परिवेश के हिसाब से शोध कार्य कर तकनीक विकसित करने की जरूरत है।

कल्पतरु एक्सप्रेस

लखनऊ, सोमवार, 10 नवम्बर 2014

कृषि विकास दर को बढ़ाने की जरूरत : राधामोहन सिंह

लखनऊ। कृषि देश की लाइफलाइन है। अगर देश को मजबूत बनाना है तो किसानों, गांवों व कृषि से जुड़े संस्थानों को मजबूत बनाना होगा। देश में औसत कृषि विकास दर चार प्रतिशत से भी कम रही है। राज्यों को कृषि विकास दर को बढ़ाने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय सभी राज्यों को हरसम्भव सहायता देने के लिए तैयार है। कृषि विज्ञान केन्द्रों में संसाधनों के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। उप्र के सात जनपदों में कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है। इन जगहों पर शीघ्र ही कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

देश के सभी जनपदों में होगा कृषि विज्ञान केन्द्र

केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह रविवार को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में विभिन्न कृषि अनुसंधान संगठनों जैसे केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केन्द्रीय मृदा एवं लवणता संस्थान, मत्स्य आनुवंशिकी संरक्षण संस्थान और विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों के अधिकारियों से उनके कार्य के दौरान आनेवाली समस्याओं पर बातचीत कर रहे थे। इन संस्थानों के उच्चाधिकारियों से कृषि मंत्री ने कहा कि अपनी जरूरतों के लिए वे सीधे तौर पर उनसे संवाद करें। किसी अन्य माध्यम को न अपनाएं। उन्होंने कहा कि जनपदों की संख्या बढ़ गई, इसीलिए अब प्रत्येक जनपद में एक-एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जाएगा। उन्होंने प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र पर एक-एक ट्रैक्टर और जीप तथा दो बाइक की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने संस्थानों के वैज्ञानिकों और अधिकारियों से कहा कि अपने संस्थान की उपलब्धियों को सबसे पहले आसपास के गांवों में फैलाएं। इससे उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं करना होगा। आसपास के क्षेत्र में स्वतः ही वैज्ञनिक शोध का प्रचार-प्रसार होगा। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालयों से बाहर निकलकर गांवों की ओर जरूर जाएं। वैज्ञानिक एक गांव को गोद लेकर देश की विकास दर और समृद्धि को और अधिक गतिमान कर सकते हैं।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली/लखनऊ । सोमवार,10 नवंबर 2014

'ब्योरा मिले तो जारी हो पैकेज'

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, सूखे के पैकेज के लिए यूपी नहीं दे रहा जानकारी

■ वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ

यूपी के 44 जिले सूखाग्रस्त घोषित होने के महीनों बाद भी राहत पैकेज का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र ने इसका ठीकरा प्रदेश सरकार के सिर फोड़ा है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने रविवार को राजधानी में कहा कि पैकेज घोषित करने के लिए केंद्र को यूपी से कुछ सूचनाओं का इंतजार है।

बारिश न होने के चलते यूपी ने 44 जिलों को सितंबर में ही सूखाग्रस्त घोषित किया था। इसके बाद सितंबर के आखिरी सप्ताह में केंद्रीय टीम ने इन जिलों का निरीक्षण कर सूखे की हकीकत जानी थी। यूपी ने केंद्र से 6000 करोड़ से अधिक का विशेष पैकेज मांगा है। केंद्रीय टीम ने यूपी से इस बारे में कुछ और जानकारियां मांगी थी। यूपी से भेजी गई जानकारियों में डीजल सब्सिडी से लेकर फसलों की बुवाई आंकड़ों को लेकर टीम ने फिर स्पष्टीकरण मांगा था। रविवार केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान में कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की बैठक के बाद कृषि मंत्री ने बताया कि यूपी से कुछ ब्यौरा मांगा गया था जो अब तक नहीं मिला है। उसको मिलने के बाद बैठक कर पैकेज की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम यूपी में नैशनल ब्रीडिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, इसके लिए राज्य सरकार से जमीन मिलने का इंतजार है।

गांवों तक पहुंचाएं शोध का फायदा

कृषि मंत्री किसान विकास केंद्र से लेकर कृषि शोध संस्थानों के काम-काज की पड़ताल करके आए थे। उन्होंने कई केंद्रों के प्रभारी से सीधे उनके यहां की गड़बड़ियों पर सवाल किए। मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों के शोध लैब और शहरों तक ही सीमित रह जा रहे हैं। इसका फायदा गांवों और किसानों तक पहुंचाए। हर कृषि वैज्ञानिक कम से कम एक गांव गोद लें और वहां खेती को बेहतर बनाने में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दें। कृषि वैज्ञानिकों से मंत्री ने कहा कि वह अपनी समस्याओं के लिए सीधे मिल सकते हैं उसके लिए माध्यम न ढूंढ़े। उन्होंने यूपी में कृषि के उन्नत बीज व प्रणाली को अपनाने में पिछड़ापन पर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दूसरे राज्य उन्नत बीज व तकनीक को हाथो-हाथ लेते हैं यूपी इसका फायदा नहीं उठा पाता। उन्होंने कहा कि साल भर में कृषि शोध संस्थानों में वैज्ञानिकों के सभी खाली पद भर दिए जाएंगे। कृषि मंत्री ने सुबह सहकार भारती के कार्यक्रम में शिरकत की और शाम को गवर्नर राम नाईक से भी मुलाकात की।

ये जिले हैं सूखा घोषित

कानपुर देहात, कानपुर नगर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, फर्रूखाबाद, सोनभद्र, महराजगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बुलंदशहर, महोबा, अमरोहा, जालौन, पीलीभीत, मऊ, जौनपुर, हमीरपुर, फैजाबाद, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, बदायूं, एटा, औरैया, चंदौली, अमेठी, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, शामली, देवरिया, कौशांबी, फतेहपुर, हापुड़, इटावा, हरदोई, उन्नाव, बांदा, आजमगढ़, बरेली, कन्नौज, झांसी, चित्रकूट, मथुरा और अलीगढ़।

NBT

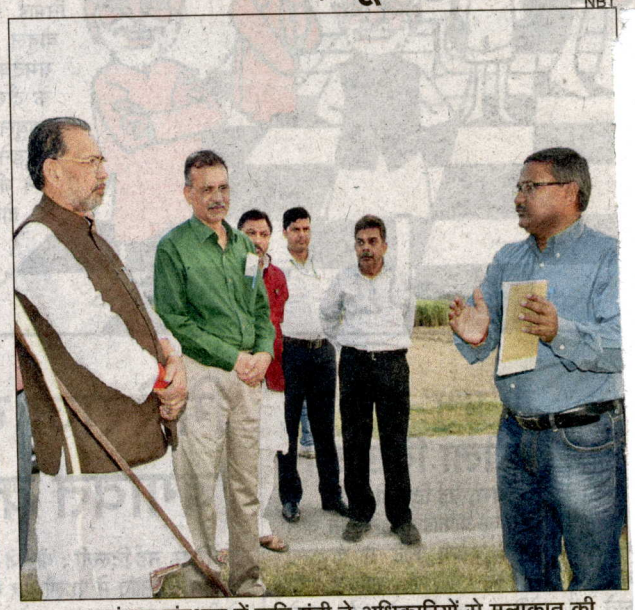

गन्ना अनुसंधान संस्थान में कृषि मंत्री ने अधिकारियों से मुलाकात की

राष्ट्रीय
www.samaylive.com
सच कहने की हिम्मत
सहारा
राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
दून • वाराणसी से प्रकाशित
लखनऊ | सोमवार • 10 नवम्बर • 2014

लखनऊ। निराला नगर स्थित माधव सभागार में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में भाग लेते केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन।

ने सभी को चलाने के लिए दो हजार करोड़ रुपये से अधिक दे दिया है।

उधर **सरोजनीनगर में** केंद्रीय कृषि, खाद्य एवं सहकारिता मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि कृषि देश की जीवन रेखा है और देश को मजबूत करने लिए कृषि से जुड़े किसानों व संस्थाओं को मजबूत करना होगा। इसलिए वैज्ञानिकों, शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी निभानी होगी। कृषि मंत्री सिंह रविवार को रायबरेली रोड स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निरीक्षण के दौरान मीडिया व अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।

इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात देश का सबसे विकसित राज्य है इसमें कृषि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। गुजरात में पिछले कुछ वर्षो में कृषि विकास 11 से 12 प्रतिशत की दर से हुआ है। जबकि देश में औसत कृषि विकास दर चार प्रतिशत से भी कम रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों को विकास की दौड़ में आगे आने लिए कृषि विकास दर को गति देनी होगी। श्री सिंह ने कृषि क्षेत्र में विकास के लिए सभी राज्यों को कृषि मंत्रालय द्वारा हर संभव मदद करेगा।

उन्होंने बताया कि बताया कि 2015 तक कृषि शोध संस्थानों में लगभग एक हजार वैज्ञानिकों की बहाली की जाएगी और जबकि तत्काल तीन सौ वैज्ञानिकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले अधिकारियों ने संस्थान द्वारा विकसित गन्ना उत्पादन तकनीकों व गन्ना तथा चीनी उद्योग को लाभकारी बनने की जानकारी दी।

इस मौके पर मौजूद कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डा. मुन्ना सिंह ने भी केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह को प्रदेश में किये जा रहे कृषि कार्यों की जानकारी दी। इस आईसीएआर शोध संस्थानों के निदेशक डा. जेके जेना, डा. एनपी सिंह, डा. वीके मिश्र, डा. एके मिश्र ने भी संस्थानों द्वारा विकसित तकनीकों की जानकारी दी।

हजार हो, एक-एक गांव से भी जुड़ो तो, चमक जाएगी खे

य कृषि मंत्री ने वैज्ञानिकों से किया आह्वान, कहा-शोध का लाभ किसानों तक पहुंच

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर) के सभागार में रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और कृषि वैज्ञानिकों के बीच वार्तालाप कुछ इसी अंदाज में रहा। कृषि मंत्री उत्तरप्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संस्थानों के वैज्ञानिकों से चर्चा करने लखनऊ पहुंचे थे।

कार्यक्रम की शुरुआत आईआईएसआर के निदेशक डॉ. एस सोलोमन द्वारा देश में गन्ना उत्पादन के हालात और जरूरत पर जानकारी से हुई। उन्होंने बताया कि आईआईएसआर में विकसित गन्ना प्रजातियों का महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक में उपयोग हो रहा है। इस पर कृषि मंत्री ने उन्हें बेहद स्पष्ट लहजे में कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की उत्पादकता महाराष्ट्र या कर्नाटक की तुलना में कम है, इसे बढ़ाने के लिए काम करें। वहीं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईएसएच) के प्रमुख वैज्ञानिक एके मिश्रा ने प्रोजेक्टर पर अपना पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन चलवाया ही था कि कृषिमंत्री सिंह ने तत्काल टोका और कहा कि सभी का प्रजेंटेशन देखने बैठे तो डेढ़ दिन लग जाएंगे। उन्होंने सीधे पूछा कि फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है। डॉ. मिश्रा संभवतः इसके लिए तैयार नहीं थे। कृषि मंत्री ने कहा कि आप किसान नहीं हैं फिर भी कोई काम करने से पहले सोचते हैं कि बिना पसीना बहाए इसका कितना दाम मिलेगा। किसान को सीधे शब्दों में क्यों नहीं बताते कि आपकी प्रजाति से उसका उत्पादन कितना बढ़ेगा। इस पर सीआईएसएच के अन्य वैज्ञानिकों ने मंच पर आकर यहां विकसित आम की लेटेस्ट किस्मों अरुणिका, अंबिका और अमरूद की किस्मों ललिता और श्वेता के बारे में बताया। कहा कि एक एकड़ में ललिता अमरूद लगाने पर 20 हजार रुपये खर्च होते हैं और यह 1 लाख रुपये की उपज देता है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने एनबीएफजीआर के निदेशक डॉ. जेके जेना के वक्तव्य को 'दीक्षांत भाषण' कहते हुए उसे रोकने के लिए कहा। उन्होंने प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार पर आश्रित न रहते हुए केंद्र के जरिये हर साल 50-50 किसानों के 10 दल हैदराबाद के नेशनल फिशरीज डवपलमेंट बोर्ड भिजवाने को कहा। साथ ही एनबीएफजीआर के वैज्ञानिकों से उत्तर प्रदेश में देश का एक फिश मार्केट विकसित करने संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। केंद्रीय मृदा लवणता शोध संस्थान के प्रभारी वीके मिश्रा, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के वीसी मुन्ना सिंह और विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के प्रभारियों से भी उन्होंने बातचीत की।

आईआईएसआर में वैज्ञानिकों को संबोधित करते कृषि मंत्री राधामोहन सिंह।

पटेल और शास्त्री के सपने साकार कर रहे मोदी

कृषि मंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री अगर ज्यादा समय जीये होते तो आज देश के किसानों को बदहाली नहीं देखनी पड़ती। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अब पीएम मोदी उनके सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं।

पास के गांवों का ध्यान रखो, वरना गोली भी चल जाती है

कृषिमंत्री ने वैज्ञानिकों और संस्थान निदेशकों को समझाया कि वे अपने संस्थान के आसपास मौजूद गांवों में भी अपने शोध का फायदा पहुंचाएं। उन्होंने वाराणसी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च (आईआईवीआर) से जुड़ा अनुभव सुनाते हुए कहा कि एक दिन पहले उन्होंने निकटवर्ती गांवों के किसानों से बात की तो पता चला कि वहां संस्थान से विकसित किसी प्रजाति की सब्जी का उत्पादन नहीं हो रहा है। सिंह ने बताया कि भागलपुर में एनटीपीसी बिजली का उत्पादन करती थी, लेकिन 4-5 किमी दूर के गांवों में बिजली नहीं थी। एक दिन 5-6 गांवों के नाराज लोग इकट्ठा हुए और एनटीपीसी के पावर स्टेशन पर हमला कर दिया। बहुत फसाद हुआ और गोलियां चल गईं। आज वहां किसानों को बिजली मिल रही है।

सियासी चुटकी लेना भी नहीं भूले कृषि मंत्री

- आईआईएसआर के विशाल कैंपस को लेकर कहा कि यूपी की एक रानी हुआ करती थी, जिनकी नजर से कुछ नहीं बचा? आपका गन्ना बच गया, इसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए।
- सात जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है और राज्य सरकार जमीन देने में या तो देरी कर रही है या दे ही नहीं रही। कृषि में राजनीति नहीं आनी चाहिए।
- यह इंटली नहीं, इंडिया है जहां सवा सौ करोड़ की आबादी को रोजगार उपलब्ध करवाना सबसे बड़ी चुनौती है।
- जो प्रदेश सरकार नारा तो प्रदेश का लगाती है, लेकिन ध्यान परिवार का रखती है, उसे भगवान देखेगा।

यूपी में नेशनल ब्रीडिंग सें खोलना चाहती है केंद्र सर

लखनऊ (ब्यूरो)। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग का माहौल बने तो यूपी में पशुपालन क्षेत्र के विकास में तेजी लाई जा सकती है। देश में एक भी नेशनल ब्रीडिंग सेंटर नहीं है। केंद्र सरकार चाहती है कि इसे दिल्ली के नजदीक ही खोला जाए। हरियाणा या किसी अन्य प्रदेश के बजाय अगर यह उत्तर प्रदेश में बने तो अधिक फायदेमंद होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने रविवार को आईआईएसआर में पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कहीं।

उन्होंने कहा, जहां ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारतीय गाय की नस्लों को अपने यहां ले जाकर 30-30 लीटर दूध देने योग्य बना चुके हैं वहीं, हम आज भी 17 प्रतिशत विदेशी नस्ल की गायों से दूध उत्पादन बढ़ाने की सोच रहे हैं। अगले 10 वर्ष में जैसी कि संभावना है औसत तापमान 1 डिग्री बढ़ चुका होगा, उसमें ये विदेशी गायें उपयोगी नहीं रहेंगी। तब भारतीय गायें ही टिक सकेंगी। इसलिए जरूरी है कि अपना देश भारतीय नस्ल की गायों का लाभ उठाए।

नेशनल ब्रीडिंग सेंटर इसमें उपयोगी कड़ी बनेगा। इसके लिए हम राज्य सरकार से जमीन चाहते हैं। उम्मीद है, इसमें राजनीति आड़े नहीं आएंगी। उप्र में सूखे को लेकर केंद्रीय टीम के दौरे पर राधा मोहन ने कहा कि टीम ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। राज्य सरकार के साथ टीम काम कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद वह एनडीआरएफ के साथ हालात से निपटने के लिए काम करेंगे।

कृषि मंत्री ने प्रदेश सरकार से मां
कहा, विदेशी नस्लों पर न रहें नि
नस्ल की गायों का लाभ उठाएं

मथुरा में गो-अनुसंधान केंद्र भी संवारेंगे

कृषि मंत्री ने कहा कि मथुरा का गो-अनुसंधान कें है। अगर राज्य सरकार उसके लिए एक प्रोजेक्ट केंद्र उसे संवारने को भी उत्सुक है। उनका मंत्रालय से सहयोग करेगा। राज्य सरकार को एक पैसा ख होगा, वे केवल प्रोजेक्ट तैयार करें और केंद्र सरक

एक हजार कृषि वैज्ञानिक भर्त

उन्होंने कहा, प्रदेश के 74 जिलों में से 67 में कृ हैं। इनमें से केवल 40 के पास ही मोटरसाइकिल अधिकतर खराब हैं। 19 के ट्रैक्टर खराब हैं तो ऐसे में ये केंद्र सेवाएं देने में पिछड़ रहे हैं। आईसी विभिन्न संस्थानों में खाली पदों को भरने की भी अगले वर्ष केंद्रीय संस्थानों में करीब एक हजार की भर्तियां की जाएंगी।

दूसरी हरित क्रांति को बताया

कृषि उपज बढ़ाने के लिए केंद्रीय संस्थानों में तैयार प्रजातियों के फसलों को अपने राज्य में लोकप्रिय राज्य सरकार का है। कृषि मंत्री ने कहा, जहां अधि सरकारें इन संस्थानों का सहयोग लेती हैं, उप्र में नहीं मिला। कुछ राज्य बीज कंपनियों को फायदा केंद्र द्वारा तैयार की जा रही प्रजातियों को दरकिना उन्होंने जेनेटिकली मॉडीफाइड फसलों पर सुप्रीम के अनुसार सरकार का रुख तय होने की बात क बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम दूसरी हरित क्रांति को अपने मंत्रालय का लक्ष्य बत कृषि केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है।